

असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग I—सण्ड । PART I—Section 1

शीधकार से प्रकाशिय PUBLISHED BY AUTHORITY

a. 212

नई किली, नृहस्पतिबार, अक्तूबर 14, 1993/आश्विन 22, 1915

No. 212) NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1993/ASHVINA 22, 1915

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 प्रगस्त, 1993

मं. 16-2/92-बाग. प्रमा. -- कृषि में प्लास्टिक्स के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय सिमिति का मूल गठन रसायन आर पैट्रोकैमिकल्स विभाग के मधीन 1981 में किया गया था। इस सिमिति का 1986 तथा फिर से 1989 में पुनर्गठन किया गया। कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग को बढ़ांवा देने के लिये इस सिमिति को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उसके प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उसके प्रयासों को और अधिक समन्वित रूप से केन्द्रित करने के लिये कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग पर राष्ट्रीय सिमिति (अब के बाद इसे सिमिति कहकर उल्लिखित किया जायेगा) को कृषि और सहकारिता विभाग के मधीन पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है:---

 सचिव (कृषि और सहकारिता) 	घट्यस
 महानिदेशक, भारतीय कृषि धनुसंधान परिषद् 	सदस्य
 सलाहकार (ङ्गिष), योजना धायीय 	सदस्य
4. श्रपर-सचिव, जल संक्षाधन मंत्रालय	सदस्य

- अध्यक्ष और प्रबन्ध निवेशक, भाई. पी. सी. एल.
- कृषि उत्पादन भ्रायुक्त,
 पंजाब सरकार
- कृषि उत्पादन धायुक्त, महाराष्ट्र सरकार
- निदेशक (जल प्रौद्योगिकी केन्द्र)
 कृषि इन्जीनियरिंग विभाग,
 तिमल नाजु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बत्रः
- वा. बी. भार. सर्मी,
 कुलपति,

 कुलपति,
 वाई. एस. परमार वागवानी कोर वानिकी
 विस्वविद्यालय,
 बोलन।
- छा. ए. एम. माइकल, कुलपित, केरल कृषि विश्वविद्यालय, विचूर
- 11. नाबार्ड का प्रतिनिक्षि

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

RGD. NO. D.L.33004/93

2321 GI/93

12. श्री सतवंत कपूर, लाजपत नगर. **भवोहर**. फिरोजपुर जिला, पंजाब। सर्वस्य

यह भी आदेश दिया जाता है कि झाम सूचना के लिये इस संकल्प की भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए।

जी एल. कौल, बागवानी भायक्त

13. की एम. एस. खनुजा,

श्रध्यक्ष.

जिला खारगीने, भारतीय किसान संघ, नृतन नगर, डाकघर जिला खारगीने, मध्य प्रदेश ।

सदस्य

सदस्य सचिव

14. बागवानी आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग

- 2. इस समिति के विचारायें विषय इस प्रकार हैं:-
- (1) उपलब्ध जलसंसाधनों के उपयोग की धनुकूलतम बनाने के विशेष संदर्भ में कृषि को उत्पादकता बढ़ाने, उत्पाद को क्वालिटी सुधारने और कटाई उपरांत हानि को कम करने के लिये कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग के लिय योजनाएं तैयार करना,
- (2) कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग की बढ़ाने के लिए राजस्य मीति, राजसहायता. किसानों के लिय सहायता भाषि जैसे उपयुक्त नीतिगत उपाय संस्तृत करना।
- (3) टपका सिचाई पद्धतियों, हर-जगहों, मॉलन, पैकेजिंग भादि के विश्रेष संदर्भ में प्लास्टिक से बनी विभिन्न वस्तुओं के उपयोग को प्रधिकाधिक प्रवास्ति करने और प्रपनाने के लिय कार्य-*मीतियौ सुञ्चाना* ।
- (4) कृषि, जल प्रबन्ध भादि में प्रयुक्त प्लास्टिक्स के लिये क्वालिटी संबंधी मानक निर्धारित करने हेतु सहायतार्थ डाटा बेस तैयार-करने के बास्ते अनुसंघान और विकास के संवर्धन की व्यवस्था
- (5) प्लास्टिक संवर्धन (प्लास्टिकल्चर) जिला कार्यक्रम और विशेषकर ष्मास्टिक संवर्धन विकास केन्द्रों और सामान्य रूप से प्लास्टिक संवर्धन केन्द्रों के समग्र विकास के कार्यान्वयन का प्रभावशाली डंग से पर्यंबेक्षण और प्रबोधन करना।
- (6) देश में प्लास्टिक के संवर्धन से संबंधित कोई भी ग्रन्य विषय।
- 3. प्रारंभ में समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की भवधि के लिये होगा। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा। समिति की भावश्यकता होने पर अन्सर लेकिन साल में कम से कम को बार बैठक होगी। समिति वार्षिक प्राधार पर सरकार को प्रपनी रिपोर्ट अस्तुस करेंगी।
- 4. समिति के लिये अपेक्षित सचिवालयी सहायता इंडियन पैटो-**डैमिकल्स** लिमिटेड से लिये गयें कार्मिकों से युक्त केन्द्रीय समन्ययन सेल द्वारा की जाती रहेगी।
- 5. समिति के कार्यों के लिये की गई याताओं के संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और गैर सरकारी सदस्यों के यादा भर्ती/ संहगाई भत्तों के ध्यय की पूर्ति समिति को दिवें गये धन में से की आयेगी। धन्य पदेन सदस्यों के संबंध में तदनुरूपी व्यय का बहुन उनके संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।
- 6. सरकार, यदि भावस्थकता हो तो समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों, मादि में उचित परिवर्तन कर सकती है।

धादेश

बादेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, संबक्षासिक बोब के प्रवासनों, लोक सभा और राज्य सभा समिवालय तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित मंद्रालयों और विभागों को भेजा जाए ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation) RESOLUTION

New Delhi, the 17th August, 1993

No. 16-2/92-HA.—The National Committee on Use of Plastics in Agriculture (NCPA) was originally set up under the Department of Chemicals & Petrochemicals in 1981. The Committee was reconstituted in 1986 and again in 1989. In order to make this Committee more effective and to focus its endeavours in a more coordinated manner for promoting the use of plastics in agriculture, it has been decided to reconstitute the National Committee on Use of Plastics in Agriculture (hereinafter referred to as the Committee) under the Deptt. of Agriculture & Cooperation, as under:

1. Secretary (Agri. & Coop.) Chairman

Director General, Indian Council of Agricultural Research.

Member

- Adviser (Agriculture) Planning Commission Member
- Additional Secretary, Ministry Water Resources

Member

- Chairman and Managing Director, Indian Petrochemicals Ltd.
- Member
- Agriculture Production Commissioner Govt. of Puniab.
- Member
- Agriculture Production Commissioner Govt. of Maharashtra.
- Member
- Director (Water Technology Centre) Deptt. of Agricultural Engineering Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

Member

- Dr. B. R. Sharma, Vice Chancellor, Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture & Forestry Solan.
- Member
- Dr. A. M. Michael, Vice Chancellor, Kerala Agricultural University, Trichur.
 - Member Member
- 11. Representative of NABARD Sh. Satwant Kapoor, Lajpat Nagar, Abohar, Ferozepur Distt., Punjab.
- Member
- Sh. M. S. Khanuja, President, Khargone Distt. B.K.S., Nutan Nagar, Post/Distt. Khargone, Madhya Pradesh.

Member

- 14. Horticulture Commissioner, DAC Member Secy.
- 2. The terms of reference of the Committee would be as under :
 - (i) To prepare plans for use of plastics in agriculture with a view to increase agricultural productivity with special reference to optimising the use of available water resources, improving quality of the product, and reducing post harvest losses.
 - (ii) To recommend suitable policy measures such as fiscal policy subsidy, assistance to farmers etc. for promotion on use of plastics in agriculture.
 - (iii) To suggest strategies for propagation and increased adoption of various plasticulture applications with special reference to drip irrigation systems, green houses, mulching packaging, etc.
 - (iv) To arrange promotion of Research and Development to build data base, to assist in prescribing quality standards for plastics used in agriculture, water management, etc.

- (v) To supervise and monitor effectively the implementation of Plasticulture Distt. Programme (PDP) and Plasticulture Development Centres (PDC) in particular and overall development of plasticulture in general.
- (vi) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.
- 3. The term of the Committee will initially be for a period of three years. The non-official members shall hold office during the pleasure of the President. The Committee shall meet as often as necessary but at least twice in a year. The Committee shall submit its reports to the Government on annual basis.
- 4. The Secretarial assistance required for the Committee will continue to be provided by the Central Coordination Cell consisting of personnel drawn from the Indian Petrochemicals Ltd.
- 5. The expenditure on TA/DA of the Vice-chancellors of Agricultural Universities and the non-cofficial members in con-

nection with the journeys undertaken on Committee's business will be met out of the funds allocated for the Committee. The corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective Departments.

6. The Government may make suitable changes in the composition and the terms of reference, etc. of the committee if required.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. L. KAUL, Horticulture Commissioner

3